

तीन वर्ष में निवेश का सबसे अच्छा केंद्र बना यूपी : योगी

इनवेस्ट यूपी की बैठक में बोले सीएम **सामान्य राज्य** नहीं उप्रे

राज्य खुरा, लखनऊ : इंज ऑफ दूइंग बिजनेस के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों-निवेशकों को आश्वस्त किया कि तान वर्ष में आपने जो महसूस किया है, उसे आगे और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन-साढ़े तीन वर्ष में यूपी निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना है। देश व दुनिया इससे वाकिफ है।

सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित इनवेस्ट यूपी की पहली बैठक में योगी ने कहा कि उप्र सामान्य राज्य नहीं, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय कुल सकल घरेलू उत्पाद में इसकी आठ फीसद भागीदारी है। यह देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और युवा राज्य भी है। यहां की लगभग 60 फीसद आबादी कामकाजी और ऊर्जावान है। इस बड़ी आबादी को हम औद्योगिक विकास के साथ समग्र विकास की संभावनाओं से जोड़कर देख सकते हैं।

जल्द ही 66 और सेवाएं हाँगी ऑनलाइन : योगी ने उद्यमियों को बताया कि निवेश मित्र पोर्टल भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो विलयरेस प्लॉटफॉर्म में से एक है। इसके माध्यम से 98 फीसद उच्च समाधान और 94 फीसद स्वीकृतियां

सूरे के विकास में सहभागी बनें : सीएम मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिल्मकी की अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी, एसोचैम के अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानन्दानी, सीआइआई नार्दन रीजन के निखिल साहनी, पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष डॉ. डाक अग्रवाल, आइआईए के अध्यक्ष पंकज कुमार, एफआईआई के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ, ट्रेड प्रमोशन कॉउंसिल ऑफ इंडिया के देयरमैन मोहित सिंगला, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष बल्देव भाई प्रजापति सहित कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ और गाजियाबाद के उद्यमियों से भी बात की। उनसे अपील की कि प्रदेश के विकास में वे सहभागी बनें।

रूपी जो आज सोचता है भारत वह कल सोचेगा एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि स्व. गोपाल कृष्ण गोखले ने सौ वर्ष पहले कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है, वह भारत कल सोचेगा। अब उप्र की दूरदर्शी योगी सरकार के अथक प्रयास के चलते यूपी जो आज सोचता है, वह भारत कल सोचेगा।

डीएम हर माह, मंडलायुक्त दूसरे माह करें उद्योग बंधु की बैठक
योगी ने निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारियों को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से उद्योग बंधु की बैठक कर स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करना होगा, जबकि मंडलायुक्त के साथ मंडल स्तर पर यह बैठक हर दूसरे महीने होंगी। समस्याओं का समय-सीमा में समाधान करने को भी कहा।

जारी की गई हैं। यहां 146 सेवाएं ऑनलाइन हैं, जबकि 66 अन्य पाइपलाइन में हैं, जिन्हें इसके साथ जोड़ा जा रहा है।

ऋण: भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के तहत पूर्व से संचालित इकाइयों को अतिरिक्त ऋण देने की योजना के तहत प्रदेश में 15 हजार करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य बनाया गया। इसमें 10,400 करोड़ रुपये का ऋण वितरित हो

चुका है। बैंकों द्वारा अब तक विभिन्न ऑनलाइन कैप के माध्यम से लगभग 3.7 लाख से अधिक इकाइयों को 13,382 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। बैंकों द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि इस वर्ष नई व पुरानी, दोनों को मिलाकर कम से कम 20 लाख इकाइयों को लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का ऋण बांटा जाएगा। अब तक 10 देशों से 50 से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें जापान, अमेरिका आदि के निवेशक हैं।